CEDSI
CENTRE OF EXCELLENCE FOR DAIRY SKILLS IN INDIA

+91 7428706078
info@cedsi.in

CEDSI TIMES

Your Skilling Partner...

इंटर डेयरी एक्सपो 2024: भारत की डेयरी इंडस्ट्री में बदलाव

"इंटर डेयरी एक्सपो 2024" का आयोजन 5 से 7 दिसंबर 2024 तक मुंबई के बॉम्बे एग्ज़ीबिशन सेंटर में किया जाएगा। यह आयोजन वीए एग्ज़ीबिशन द्वारा भारतीय डेयरी संघ (पश्चिम क्षेत्र) के सहयोग से किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में डेयरी क्षेत्र की प्रगति को प्रदर्शित करने के लिए 120 से अधिक कंपनियां भाग लेंगी, जो डेयरी वैल्यू चेन में स्थायी तकनीक, पैकेजिंग और प्रसंस्करण स्वचालन जैसी नवाचारों को प्रस्तुत करेंगी।

दुनिया के सबसे बड़े दूध उत्पादक देश के रूप में भारत ने 2023-24 में 230.58 मिलियन मीट्रिक टन दूध का उत्पादन किया, जो वैश्विक उत्पादन का लगभग 24% है। भारत का डेयरी बाजार 2030 तक 230 अरब अमेरिकी डॉलर तक बढ़ने का अनुमान है, जिसका श्रेय तकनीकी प्रगति और सरकारी सहयोग को जाता है। भारतीय डेयरी संघ के अध्यक्ष, डॉ. आर.एस. सोढ़ी ने इस क्षेत्र की ग्रामीण आजीविका में भूमिका को रेखांकित किया, जिसमें 80 मिलियन से अधिक ग्रामीण परिवार शामिल हैं, और महिलाओं के योगदान को विशेष रूप से सराहा।

इस कार्यक्रम में बी2बी सेगमेंट, वैश्विक बाजार अवसरों पर सेमिनार, एक स्टार्टअप ज़ोन, और नेटवर्किंग के अवसर शामिल होंगे। एक्सपो का समापन 5 दिसंबर को "इंटर डेयरी अवॉर्ड्स" के साथ होगा, जिसमें भारत की डेयरी इंडस्ट्री में उत्कृष्टता को मान्यता दी जाएगी।

अमूल यूरोपीय बाजार में प्रवेश के लिए तैयार

भारत की प्रमुख डेयरी ब्रांड अमूल इस महीने के अंत तक यूरोपीय बाजार में प्रवेश करने के लिए तैयार है। गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन (GCMMF) के प्रबंध निदेशक जयेन एस. मेहता ने सोमवार को यह घोषणा की। हाल ही में अमेरिका में अपने उत्पाद लॉन्च करने के बाद, यह कदम अमूल की वैश्विक विस्तार रणनीति का हिस्सा है।

अमूल ब्रांड के लिए प्रसिद्ध GCMMF ने भारत के डेयरी क्षेत्र में एक प्रमुख स्थान हासिल किया है और यह अपने विविध डेयरी उत्पादों के लिए जाना जाता है। यूरोपीय बाजार में विस्तार अमूल की अंतरराष्ट्रीय उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण और सस्ती उत्पाद प्रदान करने की महत्वाकांक्षा को दर्शाता है। यह कदम न केवल अमूल की वैश्विक बाजारों में उपस्थिति को बढ़ाएगा बल्कि इसके ब्रांड की पहचान को भी विश्व स्तर पर मजबूत करेगा।

अमूल का यूरोपीय बाजार में प्रवेश GCMMF के उस उद्देश्य के अनुरूप है जिसमें भारतीय डेयरी उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक व्यापक दर्शक वर्ग तक पहुंचाना शामिल है। यह कदम अंतरराष्ट्रीय बाजारों में गुणवत्तापूर्ण डेयरी उत्पादों की उच्च मांग को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।

एर्नाकुलम मिल्मा बनी भारत की पहली पूरी तरह सौर-शक्ति से चलने वाली डेयरी

16 करोड़ रुपये की कुल निवेश राशि के साथ, इस परियोजना को डेयरी प्रोसेसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम से 9.2 करोड़ रुपये का ऋण और केंद्र सरकार से 6.8 करोड़ रुपये की मदद प्राप्त हुई है। यह सुविधा हर साल 2.9 मिलियन यूनिट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पन्न करने का अनुमान है, जिससे मिल्मा को प्रति वर्ष लगभग 1.94 करोड़ रुपये की बिजली लागत में बचत होगी। इसके अतिरिक्त, यह हर साल लगभग 2,400 मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करेगा, जो 100,000 पेड़ लगाने के बराबर है।

एर्नाकुलम क्षेत्रीय मिल्क प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी (मिल्मा) ने भारत की पहली पूरी तरह सौर-शक्ति से चलने वाली डेयरी बनने का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया है। पशुपालन और डेयरी विकास राज्य मंत्री, जॉर्ज कुरियन ने शनिवार को मिल्मा के त्रिपुनिथुरा स्थित संयंत्र में 2 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया, जिसमें तैरते सौर पैनल, कारपोर्ट-माउंटेड पैनल और जमीनी पैनल शामिल हैं।

मंत्री कुरियन ने इस परियोजना की सराहना करते हुए इसे सतत विकास का उदाहरण बताया, यह बताते हुए कि यह परियोजना यह दर्शाती है कि कैसे नवाचार पर्यावरणीय चुनौतियों को अवसरों में बदल सकता है, जबकि मिल्मा की सभी दिन के समय ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करती है।

DAHD ने उत्तरी राज्यों में पशुपालन और डेयरी के क्षेत्र की प्रगति की समीक्षा की

पशुपालन और डेयरी विकास विभाग (DAHD) की सचिव अल्का उपाध्याय की अध्यक्षता में उत्तरी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के लिए एक क्षेत्रीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें पशुपालन और डेयरी क्षेत्र को सुदृढ़ करने में प्रगति का मूल्यांकन किया गया। इस बैठक में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के प्रतिनिधियों के साथ-साथ DAHD के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए।

बैठक में प्रमुख योजनाओं, जैसे राष्ट्रीय गोकुल मिशन (RGM), राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM), राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (NADCP), और पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम (LHDCP) की समीक्षा की गई। चर्चा में छह माह में टीकाकरण को तेज़ करने, सीरो-सर्विलांस सुधारने और फुट एंड माउथ डिजीज (FMD) मुक्त क्षेत्र बनाने पर जोर दिया गया।

DAHD सचिव ने डेयरी प्रसंस्करण क्षमता बढ़ाने और उत्पादों को विविधित करने की आवश्यकता पर बल दिया, साथ ही राज्यों से बकरियों, सूअरों और मुर्गियों के क्षेत्र में चारा सहकारी समितियों और उद्यमिता को बढ़ावा देने का आह्वान किया। मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों (MVUs) का संचालन, पशु कल्याण समितियों का गठन, और AHIDF का उपयोग wealth creation के लिए रणनीतिक प्राथमिकताओं के रूप में उजागर किया गया।

बैठक में 21वीं पशुधन गणना के महत्व को भी रेखांकित किया गया, और हितधारकों से उन्नत प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके इसके सफल कार्यान्वयन की अपील की गई। DAHD सचिव ने उत्तरी राज्यों से आग्रह किया कि वे निधियों का बेहतर उपयोग करें और रोगों की रोकथाम के उपायों को मजबूत करें, ताकि पशुधन क्षेत्र अधिक सक्षम और सशक्त बने।

अमूल और प्रमुख कंपनियों ने ओडिशा के डेयरी और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों में ₹250 करोड़ का निवेश करने की घोषणा की

गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड (अमूल) ने ओडिशा के डेयरी क्षेत्र में ₹250 करोड़ का निवेश करने की योजना की घोषणा की है, जिससे राज्य के 30 लाख लीटर प्रति दिन के दूध आपूर्ति अंतर को दूर किया जा सकेगा। अमूल के प्रबंध निदेशक आर.एस. सोढी ने यह घोषणा नई दिल्ली में वर्ल्ड फूड इंडिया 2017 के दौरान एक सेमिनार में की। ओडिशा, जो वर्तमान में भारत में अमूल का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है, इस निवेश से बड़ी लाभ की उम्मीद कर रहा है।

अन्य कंपनियों ने भी ओडिशा के कृषि-व्यवसाय और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों में निवेश करने का इरादा व्यक्त किया। केवेंटेर एग्रो लिमिटेड के एमडी मयंक जालान ने मक्का प्रसंस्करण, केले की खेती और एक खाद्य प्रसंस्करण प्रयोगशाला में परियोजनाओं का प्रस्ताव रखा। टाटा ग्लोबल बेवरेजेस लिमिटेड ने ओडिशा को ₹40 करोड़ के चाय पैकिंग यूनिट के लिए संभावित स्थल के रूप में पहचाना, जिससे 400 नौकरियां सृजित होंगी।

इस बीच, एजीटी फूड्स और इसके कैनेडियन सह-प्रोमोटरों ने पराडीप के पास ₹250 करोड़ का खाद्य प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने की योजना की घोषणा की। आईटीसी और उसकी सहायक कंपनी, टेक्निको टेक्नोलॉजीज ने खुर्दा में अपने खाद्य संयंत्र परियोजना को शीघ्र पूरा करने का वादा किया।

ओडिशा की अपील को उजागर करते हुए मंत्री प्रद्युत सामल ने राज्य की खाद्य प्रसंस्करण नीतियों, डेरा और रायगढ़ा में मेगा फूड पार्कों और निवेशकों के लिए एकल-खिड़की सुविधा का उल्लेख किया। अतिरिक्त मुख्य सचिव एल.एन. गुप्ता ने ओडिशा की कृषि-जलवायु विविधता और अधिशेष अनाज और सब्जी उत्पादन का उल्लेख करते हुए इसे खाद्य प्रसंस्करण निवेशों के लिए प्रमुख गंतव्य बताया।

केंद्रीय मंत्री ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में निवेशकों की बैठक 2024 का उद्घाटन किया, डेयरी क्षेत्र के अवसरों को उजागर किया

मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने अंडमान और निकोबार प्रशासन के साथ मिलकर "निवेशकों की बैठक 2024: मत्स्य पालन और जलकृषि में निवेश के अवसर" का आयोजन किया, जिसमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के विभिन्न क्षेत्रों, विशेषकर डेयरी, में संभावनाओं को प्रदर्शित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह ने किया, जिन्होंने भारत सरकार द्वारा समर्पित पहल और निवेशों की बात की, जो संबंधित क्षेत्रों को मजबूत करने के लिए चलाए जा रहे हैं।

लफ्टिनेंट गवर्नर एडमिरल डी.के. जोशी ने लॉजिस्टिक चुनौतियों को स्वीकार करते हुए इन समस्याओं को हल करने के लिए उठाए गए कदमों की घोषणा की, जिनमें दक्षिण-पूर्व एशिया के लिए सीधी उड़ानों का संचालन भी शामिल है, जिससे व्यापार को सुगम बनाया जा सके।

कार्यक्रम में कृषि क्षेत्र के अवसरों को भी उजागर किया गया, जिसमें आधुनिक बुनियादी ढांचे और सतत प्रथाओं के विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया। निवेशकों और हितधारकों से दूध उत्पादन और प्रसंस्करण में अप्रयुक्त संभावनाओं का अन्वेषण करने का आह्वान किया गया, जो क्षेत्र में एक आत्मनिर्भर, संसाधन-कुशल और निर्यातोन्मुख डेयरी क्षेत्र के लिए सरकार के दृष्टिकोण से मेल खाते हैं।

मंत्री ने प्रमुख कार्यक्रमों जैसे पीएमएमएसवाई, पीएम-एमएसकेवाई और एफआईडीएफ का उल्लेख किया, जिन्होंने 2015 से अब तक ₹38,572 करोड़ से अधिक के निवेश को आकर्षित किया है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को दक्षिण-पूर्व एशिया के करीब स्थित मत्स्य पालन और डेयरी निर्यातों के लिए एक केंद्र के रूप में स्थापित करने के प्रयासों में जुटी हुई है।

एर्नाकुलम मिल्मा: भारत का पहला पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाला डेयरी सहकारी संस्थान बनकर एक मील का पत्थर स्थापित

एर्नाकुलम क्षेत्रीय दूध उत्पादक सहकारी समाज (मिल्मा) ने इतिहास रचते हुए भारत का पहला पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाला डेयरी सहकारी संस्थान बनने का गौरव प्राप्त किया है। पशुपालन और डेयरी विकास राज्य मंत्री, जॉर्ज कुरियन ने मिल्मा के त्रिपुनिथुरा स्थित केंद्र में 2 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया।

इस ₹16 करोड़ की परियोजना में विभिन्न प्रकार की सौर ऊर्जा स्थापित की गई है, जिसमें 8 किलोगावाट की तैरती पैनल, 102 किलोगावाट की कारपोर्ट-निर्मित पैनल और 1,890 किलोगावाट की ग्राउंड-माउंटेड पैनल शामिल हैं। इस पहल को डेयरी प्रसंस्करण और बुनियादी ढांचा विकास योजना (DIDF) के तहत ₹9.2 करोड़ का ऋण और ₹6.8 करोड़ का केंद्रीय सरकार से अनुदान प्राप्त हुआ।

मंत्री जॉर्ज कुरियन ने इस परियोजना की सराहना करते हुए इसे सतत विकास का एक उत्कृष्ट उदाहरण बताया, जो यह दिखाता है कि किस प्रकार इस्तेमाल न होने वाली दलदली भूमि को एक नवीकरणीय ऊर्जा केंद्र में बदला जा सकता है, बिना पर्यावरणीय संतुलन को नुकसान पहुंचाए।

यह संयंत्र वार्षिक रूप से 2.9 मिलियन यूनिट नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन करेगा, जिससे ₹1.94 करोड़ की ऊर्जा लागत की बचत होगी और 2,400 मीट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी, जो 100,000 पेड़ लगाने के बराबर है।

मिल्मा का यह सौर संयंत्र न केवल दिन के समय अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करेगा, बल्कि अतिरिक्त ऊर्जा को ग्रिड में भी भेजेगा, जिससे क्षेत्र की बिजली की आवश्यकता को और समर्थन मिलेगा। यह ऐतिहासिक उपलब्धि डेयरी क्षेत्र की हरी-भरी नवाचार में अग्रणी भूमिका को प्रदर्शित करती है।

सीईएएसआई गतिविधियाँ

सीईएएसआई और नुज़ीवीडू सीड्स ने डायरेक्ट सीडेड राइस पहल के साथ सतत कृषि में कीर्तिमान स्थापित किया

हरियाणा के कृषि क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में, राज्य ने हर्बिसाइड-टॉलरेंट (एचटी) बासमती चावल की किस्मों का उपयोग करके 1015 एकड़ में डायरेक्ट सीडेड राइस (डीएसआर) पद्धति को सफलतापूर्वक लागू किया है। इस पहल को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईएआरआई) द्वारा विकसित किया गया और नुज़ीवीडू सीड्स लिमिटेड के प्रमुख बीज ब्रांड, पीबी-1985 गोल्डस्टार एचटी और पीबी-1979 सुपरस्टार एचटी के माध्यम से वितरित किया गया, जिससे किसानों को उल्लेखनीय लाभ प्राप्त हुए।

हरियाणा में डीएसआर पद्धति के तहत एचटी बासमती चावल की अपनाई से प्रति एकड़ 1.5-2 क्विंटल उपज में वृद्धि हुई, किसानों को प्रति एकड़ ₹5,000 की बचत हुई, और उन्हें ₹4,000 का सरकारी बोनस मिला। इस पद्धति ने पानी की बचत की और खेती का समय कम किया, जिससे सतत कृषि को बढ़ावा मिला।

प्रमुख परियोजना विशेषताएँ:

यह पहल हरियाणा सरकार, कृषि विभाग, नुज़ीवीडू सीड्स लिमिटेड, हिसार कृषि विश्वविद्यालय के सहयोग से और भारत में कृषि कौशल के लिए उत्कृष्टता केंद्र और वराहा एग (एक कार्बन वॉथड्रॉल कंपनी) के समर्थन से चलाई गई है। एचटी तकनीक बासमती में डीएसआर के त्वरित अपनाने का मार्ग प्रशस्त कर रही है, जिससे चुनौतियों का समाधान किया जा रहा है और किसानों को उन्नत कृषि समाधान प्रदान किए जा रहे हैं।

प्रमुख गतिविधियाँ और उपलब्धियाँ:

1. कुल बैठकें आयोजित: विभिन्न जिलों में 200 सत्र।
2. कवर किए गए जिले: फतेहाबाद, हिसार, जींद, कैथल, करनाल, पानीपत, सिरसा, सोनीपत।
3. किसानों की भागीदारी: प्रत्येक सत्र में लगभग 6,000+ किसान उपस्थित।
4. कुल प्रदर्शन: 1015 प्रदर्शन किए गए।

कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएँ:

डीएसआर की सफलता की कहानी हरियाणा के माननीय राज्यपाल के साथ एक विशेष प्रस्तुति में साझा की गई, जिसमें कृषि और किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस) डॉ. राजा शेखर वुंद्रु, आईएएस, और अन्य प्रमुख गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए।

कार्यक्रम में शामिल:

किसानों की सफलता और भविष्य की दृष्टि:

15 प्रमुख किसानों द्वारा साझा की गई प्रतिक्रियाओं और सफलता की कहानियों ने एचटी बासमती चावल को अपनाने के आर्थिक, व्यावहारिक, और पर्यावरणीय लाभों को उजागर किया। हरियाणा ने डीएसआर और हर्बिसाइड-प्रतिरोधी तकनीक के लाभों को प्राप्त करने में भारत का अग्रणी राज्य बनकर एक मानक स्थापित किया है। यह अग्रणी दृष्टिकोण अन्य राज्यों के लिए एक मॉडल के रूप में कार्य करता है, यह दिखाते हुए कि आधुनिक कृषि प्रथाओं को प्रभावी ढंग से कैसे लागू किया जा सकता है।

हम कौन हैं?

सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस फॉर डेरी स्किल्स इन इंडिया (सीईडीएसआई) "सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस फॉर एग्रीकल्चर स्किल्स इन इंडिया (सीईएएसआई)" के तहत काम कर रहा है, यह एक स्वायत्त संगठन है जो "**एग्रीकल्चर स्किल कौंसिल ऑफ़ इंडिया (ASCI)**" के तत्वावधान में काम कर रहा है। कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के संगठित और असंगठित क्षेत्रों में लगे किसानों, वेतनभोगी श्रमिकों, स्व-रोज़गार पेशेवरों, विस्तार श्रमिकों आदि के कौशल और क्षमता निर्माण के लिए **कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई**) के तहत काम करना।

सीईएएसआई कृषि के विभिन्न उप-क्षेत्रों में उत्कृष्टता केंद्रों का एक शीर्ष संगठन है।

- सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस फॉर डेरी स्किल्स इन इंडिया (सीईडीएसआई)
- सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस फॉर हॉर्टिकल्चर स्किल्स इन इंडिया (सीईएचएसआई)
- सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस फॉर फार्म मेकेनिज़शन स्किल्स इन इंडिया (सीईएफएमआई)

सीईडीएसआई सदस्यता उद्योग के नेताओं, नीति निर्माताओं, विकास चिकित्सकों, डेयरी वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं, छात्रों और किसानों को डेयरी उद्योग के लिए आसन्न महत्व के मुद्दों पर बहस और चर्चा करने के लिए एक अनूठा मंच प्रदान करेगी।

+91 7428706078

info@cedsi.in

www.cedsi.in Follow us on Facebook Cedsi Dairyskills Follow us on Twitter @CEDSI_India Follow us on Instagram @cedsi_india Follow us on linkedin Cedsi dairy COE

Centre of Excellence for Dairy Skills in India

Join Our Membership Drive and Get Benefits of

- Platform to interact with other members in the sector
- Networking opportunities with corporate leaders and government authorities
- Special costs of training in Skill India Certified Programmes
- Access to our Journal and Publications
- Expert advice in day-to-day operations and management of livestock /farm productions
- Free registration on the job portal and regular updates on job vacancies in the sector
- Recognize your organization with CEDSI Yearly Awards and Recognition
- Chance to reach across the board through advertising in our press releases, news and articles
- Consultative and advisory services to help members
- Consulting and advisory services to help members
- Periodic e-newsletter for the latest news, govt. announcement and schemes in dairy sectors
- Updates on training programs of CEDSI and access to the training calendar

Who Can Become a Member -

Corporates/ Cooperatives

NGO's/CSR Foundations

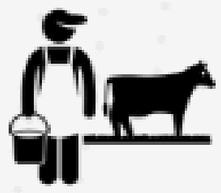

Dairy Farmers

Students

Professional

www.cedsi.in

17th July 2024

@cedsi_india

CEDSI : रविविंग स्किल्स एंड जनरेटिंग लाइवलीहुड

किसानों/छात्रों/उद्यमियों के लिए कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम

- डेयरी किसान / उद्यमी
- डेयरी फार्म पर्यवेक्षक
- डेयरी कार्यकर्ता
- पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता
- कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन
- पशु चिकित्सा क्षेत्र सहायक
- पशु चिकित्सा नैदानिक सहायक
- बछड़ा पालन
- कृषि उपकरण तकनीशियन
- डेयरी फार्म अर्थशास्त्र और प्रबंधन
- उद्योग संरेखित प्रमाणन कार्यक्रम (बेरोजगार युवा और छात्र)

एफपीओ उन्मुख प्रशिक्षण कार्यक्रम

- उत्पाद प्रौद्योगिकी और प्रक्रियाओं पर एफपीओ सदस्य अभिविन्यास।
- एफपीओ मार्केट लिंकेज
- एफपीओ शासन
- एफपीओ लेखा

डेयरी कॉरपोरेट्स और सहकारी समितियों के लिए प्रमुख कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम

- चिलिंग प्लांट तकनीशियन
- बल्क मिल्क कूलर ऑपरेटर
- ग्राम स्तरीय दुग्ध संग्रह केन्द्र पर्यवेक्षक
- दूध परीक्षक
- ग्रीन हाउस गैसों का शमन
- दूध की गुणवत्ता आश्वासन
- मिल्क डिलीवरी बॉय
- दूध खरीद और इनपुट पर्यवेक्षक
- डेयरी उद्योग में अपशिष्ट प्रबंधन
- चारा और चारा प्रबंधन
- स्वच्छ दूध उत्पादन
- निर्णय समर्थन प्रणाली / डेटा विश्लेषिकी

सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस फॉर डेरी स्किल्स इन इंडिया